attending all the meetings, I am not aware that it was decided in the BAC.

श्री राम विलास पासवान: फर्स्ट के बुलिटन में निकला था कि शनिवार वर्किन्ग डे रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक्सप्लेनेशन हुआ था। आपने पूछा कि शनिवार को सैशन कैसे रखा गया। उन्होंने कहा कि आर्डिनेंसिज वगैरह हैं, इसलिए रखा गया है।

Something like this was taken up in the BAC. This is what happened.

श्री रामावतार शास्त्री : आखिर ह्विप्स कांफरेंस करने का मतलब क्या है ? उनकी राय तो लेनी चाहिए।

SHRI BUTA SINGH : I am going to hold a meeting with the Chief Whips of all the political parties in the House.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैं भी उसमें शामिल हुआ था। यह कहा गया कि हम उनके साथ कोआपरेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज इसका सबूत यह है कि इनकी तरफ से लापरवाही हो रही है। मैं सिर्फ ह्विप्स कान्फरेंस की बातों की याद दिला रहा हूं।

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : میں بھی اس میں شامل ہوا تھا۔ یہ کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریشن نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی طرف سے لاپرواہی ہو رہی ہے۔ میں صرف وہپس کانفرنس کی باتوں کی یاد دلا رہا ہوں۔

SHRI BUTA SINGH : I have promised to Shri Satish Agarwalji that we will have a Whips' meeting.

MR. SPEAKER : We will have a lunch meeting.

BUSINESS OF THE HOUSE

11.11 hrs.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in the House during the week commencing 5th March, 1984, will consist of :—

1. General discussion on the Railway Budget for 1984-85.
2. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Prevention of Damage to Public Property Ordinance, 1984 and consideration and passing of the Prevention of Damage to Public Property Bill, 1984, as passed by Rajya Sabha.
3. General discussion on the General Budget for 1984-85.

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी द्वारा आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तुत कार्य सूची में निम्न दो विषयों का समावेश करवाना चाहता हूं।

1. फारेस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट 1980 के प्राविधानों के कारण अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के फलस्वरूप देश के अधिकांश भागों विशेषकर पर्वतीय व जनजाति वाले क्षेत्रों में निर्माण व विकास के कार्य लगभग 3 साल से ठप्प पड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों के विकास में एक भयंकर गतिरोध पैदा हो गया है। जनता में इस ऐक्ट के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त है। इसका दुष्प्रभाव हमारी समूची फारेस्ट पालिसी पर पड़ रहा है।

2. आने वाले वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश को योजना परिव्यय में वांछित वृद्धि न किए जाने का दुष्प्रभाव वहां की कई राष्ट्र उपयोगी परियोजनाओं पर पड़ना निश्चित है। ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। योजना मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के क्षेत्र वाले विकास कार्यों के लगभग ठप्प पड़ जाने की संभावना पैदा हो गई है। अत: इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी संसद में चर्चा आवश्यक है।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए संसदीय कार्य मन्त्री

को निम्नलिखित दो सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं :

1. गैर कानूनी प्रवासियों का पता लगाने के लिए बनाए गए न्यायिक पंचाटों की प्रक्रिया पर असम आन्दोलनकारियों ने असहमति दिखाई है कि इन पंचाटों की प्रक्रिया मानने से 1971 से पहले आकर बसे सभी लोगों को कानूनी दर्जा मिल जाएगा। आन्दोलन का नया कार्यक्रम बन रहा है तथा उसे अखिल भारतीय समर्थन दिलाने के लिए 14 फरवरी को देश के कई भाग में "काला दिन" भी मनाया गया था। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में आन्दोलन का असर बढ़ रहा है। अप्रवासियों के विषय में सब की चिन्ता एक जैसी है। आन्दोलनकारियों को बातचीत के रास्ते पर लौटाने से आन्दोलन जनित कटुता समाप्त होगी।

2. बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में चाइबासा अनुमंडल के मुंडा जनजाति के प्रशासन के लिए अंग्रेजी राज्य में ही बंगाल रेगुलेशन की धारा 13 के अन्तर्गत विल्किन्संस रूल्स में 1833 में ही उन की परम्परागत संस्था को मान्यता दी गई थी तथा उन्हें कुछ पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार सौंपे गये थे तथा इस भूभाग को कोल्हान नाम दिया गया था। गणतंत्र बन जाने के बाद उन संस्थाओं की उपेक्षा की जा रही है और उनके अधिकारों में राज्य प्रशासन का हस्तक्षेप आरम्भ हो गया है। यह जनजाति अपनी परम्पराओं में अनावश्यक हस्तक्षेप को अपनी संस्कृति को नष्ट किए जाने का प्रयास मानती है तथा इसका विरोध करती है। यह भाग धीरे धीरे संवेदनशील बनता जा रहा है तथा यह जनजाति सरकार से असन्तुष्ट होकर उसके इरादे पर सन्देह करने लगी है। अत: मेरा सुझाव है कि इस समस्या को समय रहते सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों में मध्य प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और निर्माण की मांग की जा रही है जिनकी ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है।

इन्दौर से उज्जैन, रतलाम, बम्बई के बीच सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करने की आवश्यकता है जिसकी संसदीय याचिका समिति ने भी अनुशंसा की है किन्तु उसे अब तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार उज्जैन से इन्दौर के बीच तेज गति की मीटरगेज रेल सेवा, जोकि इन दो नगरों की 63 किलोमीटर दूरी को अधिकतम 80 मिनट में तय करे, चलाने की आवश्यकता है। उज्जैन और इन्दौर मध्य प्रदेश के दो प्रमुख नगर हैं। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और प्रशासनिक दृष्टि से इन महत्वपूर्ण नगरों के बीच सुगम और सुविधाजनक यातायात से जनता को आवागमन को सुरक्षित त्वरित बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार उज्जैन, आगर, सुसनेर, झालावाड़, पाटन, रामगंज मंडी तक नयी रेल लाइन का सर्वेक्षण कर निर्माण किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे कोच सुधार और निर्माण कारखाने की स्थापनार्थ शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए उपरोक्त बातों को शीघ्र पूरा करे।

2. देश में तथा मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग संकट में है। जहां एक ओर इन्दौर के होप टेक्सटाइल के बन्द होने के कारण हजारों मजदूर बेकार और बेरोजगार हो गए हैं, वहीं उज्जैन के विनोद और विमल मिलों की हालत भी ठीक नहीं है। इनके कभी भी बन्द हो जाने का खतरा बना हुआ है जिसके कारण हजारों मजदूरों की जीविका संकट में हो जाने का भय है।

अतएव टेक्सटाइल मिलों की ओर केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

उक्त विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :

अध्यक्ष महोदय, आज की मद संख्या 1 के अन्तर्गत मैं अगले सप्ताह में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना चाहता हूं।

जैसा कि सदन को मालूम है कि पिछड़े वर्गों के हितों के लिए गठित बी०सी० मण्डल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को राष्ट्रपति को पेश की। उसके बाद सदन में तीन बार उस पर बहस हुई और गृह मन्त्री ने हमेशा सदन को आश्वासन दिया कि सरकार मण्डल कमीशन की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है लेकिन अफसोस है कि चार वर्ष हो गए लेकिन अभी तक मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। पिछले साल 50 संसद सदस्यों ने इस मांग को लेकर अपनी गिरफ्तारी दी। आश्चर्य है कि जब दोनों पक्ष के सदस्य एकमत से भावना व्यक्त कर चुके हैं तो भी सरकार मण्डल कमीशन की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू कर रही है।

2. पूरे देश में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। काफी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की हत्या की जा चुकी है। दिल को दहलाने वाले पिछले दिनों पिपरिया एवं मुंगेर में सामूहिक हत्या काण्ड हुए। यही स्थिति दूसरे राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में भी है। यहां तक कि भारत की राजधानी दिल्ली में लोगों का जन जीवन बिल्कुल असुरक्षित हो गया। जब से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से स्थिति और खराब हो गई है। पूरे देश में लोगों का जन जीवन असुरक्षित हो गया है। अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा कमजोर वर्गों पर जुल्म एवं अत्याचार बढ़ रहे हैं।

अत: बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सदन में चर्चा करायी जाए।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : I request the Minister for Parliamentary Affairs to include the following subjects in the Business of next week.

(1) Concern about Indians' security following developments in South West Asia which have led to increasing military presence of big powers in the Indian ocean.

(2) Debate over Land Acquisition (Amendment) Bill, which was once included in the list of Business in the last Budget Session. This legislation, if passed, would immensely benefit the farmers.

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Srinagar) : The following item may please be included in the Business for the next week :

The green lush magnificent forests ever decreasing in density are a wealth of immense value to our country. But exploitation of forests for timber and sleepers for railway tracks etc. and fuel for cooking purposes is gradually diminishing the wealth and with it the charm and flora and fauna of Himalayas. Jammu and Kashmir being a poor state is unwill:ng and simply to sustain its income from this important source allows felling of trees in large numbers every year. The State would be happy if entire forests of the State are preserved for all practical purposes, and unnecessary exploitation of jungles and its products like resin stops which cuts at its roots. Let the Centre come forward and reciprocate this offer by compensating the losses from the forests every year ; and giving additional grants and taking necessary measures in this regard. The lovely deep rich forests thus saved from deforestation shall be national assets and can be changed with National parks.

SHRI CHANDRA PAL SHAILANI (Hathras) : The following item should be included in the business for the week commencing 5 March, 1984.

The grades and scales of pay of the teachers of the Schools maintained by the Aligarh University were brought at par with the grades of the teachers of the Central Schools in 1969. The teachers of the Central School were given Selection Grade 1974 with retrospective effect from 1st January, 1971. The University Grants in Commission granted the Selection Grade to the teachers of Schools of the Aligarh

University with effect from 1st January, 1973. The Executive Council of A.M.U. also sanctioned this grade. But it has not been implemented so far causing great hardship to the teachers of A.M.U. This is a clear case of gross injustice. Some of the teachers who are entitled for Selection Grade have died and some of them have retired.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : The City of Bombay and the coastal regions of Maharashtra are severely lacking in water for drinking and for irrigation. However the Bangalore the Deccan Herald reported in a despatch on February 24th that Saudi Arabia and Israel have developed the Reverse-Osmosis process for desalinating sea water to make it fit for drinking as well as for irrigation. By use of natural gas for generating power, the cost of producing potable water from sea can be made cheap. Since we are flaring natural gas in Uran (near Bombay) and in coastal Maharashtra, because the gas is in surplus therefore, we can desalinate sea water cheaply in the Bombay area. Cost of electricity is the main factor in desalination process.

Desalination of sea water is the answer to Bombay's drinking water problem. Since the technology has to be imported from either Saudi Arabia or Isreal, therefore, the Central Government will have to take the initiative in this area.

I demand a discussion, therefore, on the methods to solve the drinking water and irrigation problem next week. Furthermore, the Government have made a commitment in the United Nations to observe the 1980 as the decade of water supply.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central) : I would like to suggest the following items for inclusion in the list of business :

1. Due to paucity of funds Central Government decided to provide basic amenities to slum dwellers numbring 3.5 crores under Slum Improvement Scheme instead of Slum Clearance Scheme which aimed at housing slum dwellers.

When slum upgradation programme with the World Bank which provides basic amenities to the slum dwellers is already adopted by the Government 'Habitat India', a private concern has come forward with a scheme to house 3 million slum dwellers of Bombay by constructing five storey buildings, costing minimum Rs. 1200 crores.

I would request the Government to place Habitat Plan Before the House for full discussion.

2. In spite of assurance given by the Government in the House there is no improvement in the employment situation of women or on their working conditions. On the contarary, women are belng thrown out of jobs which is seriously affecting their status. As a result, Anganwadi teachers in Delhi courted arrest to press for their just demands as a last resort. Nurses are on march to fight against the inhuman working conditions. The women workers from Bombay textile industries are not being taken back.

Hence a discussion on employment of women is necessary.

SHRI BUTA SINGH : However much I would have liked the subjects mentioned by hon. Members to be discussed in this House, Sir, as you know, we have discussed the Motion of Thanks on the President's Address and the scope of the discussion was very wide. We are going to have another opportunity when we discusss the General Budget. Most of these items can get covered in that. But I would like to place these subjects which have been highlighted by the hon. Members before the Business Advisory Committee and also before you and in case it is possible for the Business Advisory Committee to find time for such subjects, we will have no objection. Let these be referred to the Business Advisory Committee. We will try to see that if we can find time we will discuss. I am sorry, at the moment it is not possible for me on my own to include these items in the List of Business which I have just now concluded. With these words, I request the hon. Members to please wait till the Business Advisory Committee finds time for such subjects.

SHRI RAM VILAS PASWAN : (Hajipur) : What about the Mandal Commission's Report, Sir ?